CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

CEASI TIMES

हिन्दी

सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स

CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEFMI
Centre of Excellence for Farm Mechanization Skills in India

CEHSI
Centre of Excellence for Horticulture Skills in India

CEASI TIMES

एग्रीकल्चर इनसाइट्स

भारत का खाद्यान्न उत्पादन FY25 में पहुँचा 1,663.91 लाख टन, 106 लाख टन की बढ़ोतरी

भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में 106 लाख टन बढ़कर 1,663.91 लाख टन हो गया है। रबी फसलों का उत्पादन 2023-24 के 1,600.06 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 1,645.27 लाख टन हो गया, यह जानकारी कृषि मंत्रालय ने दी है। यह वृद्धि देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और घरेलू व वैश्विक मांगों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

कृषि को बढ़ावा देने के लिए पुणे में एक राष्ट्रीय स्तर की "क्लीन प्लांट प्रोग्राम" प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। यह प्रयोगशाला मौलिक पौधों पर शोध करेगी ताकि रोगमुक्त नर्सरी और उच्च गुणवत्ता वाले बीज तैयार किए जा सकें।

सरकार किसानों और अनुसंधान संस्थानों के बीच संबंध मजबूत करने की योजना बना रही है। देशभर के 113 से अधिक ICAR संस्थान, जिनमें महाराष्ट्र के 11 शामिल हैं, इस विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इन प्रयासों का उद्देश्य उत्पादन दक्षता बढ़ाना, लागत घटाना और देशभर में टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करना है।

छह पारंपरिक कृषि प्रणालियों को वैश्विक मान्यता, स्थिरता और विरासत के लिए सराहना

खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने ब्राजील, चीन, मेक्सिको और स्पेन की छह पारंपरिक कृषि प्रणालियों को ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स (GIAHS) में शामिल किया है। यह मान्यता उनकी टिकाऊ खेती, जैव विविधता संरक्षण और सांस्कृतिक महत्व के लिए दी गई है। अब दुनियाभर में GIAHS स्थलों की कुल संख्या 95 हो गई है।

हर प्रणाली में अनूठी पारिस्थितिकीय विशेषताएँ हैं—जैसे शुष्क जलवायु में नमी को बनाए रखने के लिए ज्वालामुखीय राख का उपयोग, सैकड़ों वर्षों पुरानी फसल-पशुधन समाकलन पद्धति, और बीज संरक्षण की पारंपरिक तकनीकें।

FAO ने इन प्रणालियों को जलवायु और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच नवाचार और लचीलापन का आदर्श बताया है। ये "जीवंत परिदृश्य" पारंपरिक ज्ञान और जैव विविधता को बचाकर टिकाऊ खेती की दिशा में वैश्विक सीख प्रदान करते हैं।

इस सूची में शामिल नई प्रणालियों में ब्राजील की छांव में उगाई जाने वाली एरवा-मैटे एग्रोफॉरेस्ट्री, चीन की तीन प्रणालियाँ—देचिंग की मोती शंख पालन प्रणाली, फुडिंग की सफेद चाय संस्कृति, और गांसू के प्राचीन नाशपाती बाग—मेक्सिको की मेटेपांटल सीढ़ीनुमा खेती, और स्पेन के लैंजारोटे द्वीप की ज्वालामुखीय राख पर आधारित खेती शामिल हैं।

CEASI TIMES

चेरलापल्ली जेल में शुरू हुआ मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण: बंदियों को मिलेगा आजीविका का नया जरिया

तेलंगाना के चेरलापल्ली बंदी कृषि कॉलोनी में मधुमक्खी पालन (एपिकल्चर) प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य बंदियों को जेल में रहते हुए शहद उत्पादन से जुड़ी व्यावहारिक कौशल सिखाना और रिहाई के बाद उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।इस प्रशिक्षण में छत्तों की देखभाल, कॉलोनी प्रबंधन, शहद संग्रहण, मोम प्रसंस्करण और उत्पाद विपणन जैसे प्रमुख विषयों को शामिल किया गया है।

कॉलोनी में पहले से मौजूद फूलों वाले पौधे इस कार्य के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के ज़रिए न केवल स्थायी आजीविका के अवसर तैयार किए जा रहे हैं, बल्कि यह भी जागरूकता फैलाई जा रही है कि विश्व की लगभग 75% खाद्य फसलों का परागण मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। प्रशिक्षण से बंदियों में अनुशासन, टीमवर्क और जिम्मेदारी विकसित हो रही है।

इस पहल को तेलंगाना बी हब सोसाइटी का तकनीकी सहयोग और उद्यान विभाग की सब्सिडी मिल रही है। इच्छुक बंदियों को रिहाई के बाद एपिकल्चर को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।यह नवाचार पर्यावरण संरक्षण और कौशल विकास को एक साथ जोड़ने वाली एक अनूठी पहल है, जो सुधारात्मक व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है।

तमिलनाडु में सिंचाई और उत्पादकता बढ़ने से कृषि विकास दर 5.66% तक पहुँची

तमिलनाडु ने 2021 से 2024 के बीच औसतन 5.66% की कृषि विकास दर हासिल की है, जो 2012 से 2021 के बीच की 1.36% औसत दर की तुलना में काफी अधिक है। सरकार ने खेती योग्य जमीन बढ़ाने और सिंचाई ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया, जिससे सिंचित क्षेत्र 2020–21 के 36.07 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2023–24 में 38.33 लाख हेक्टेयर हो गया।

'कलैग्नर ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट योजना' के तहत 47,286 एकड़ परती जमीन पर ₹786.86 करोड़ की लागत से खेती शुरू की गई, जिससे 51 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ। राज्य रागी और अमरूद की उत्पादकता में पहले स्थान पर है, जबकि मक्का, गन्ना, इमली, कसावा, चमेली और तिलहन में दूसरे स्थान पर है।

पांच कृषि बजटों के जरिए कुल ₹1,94,076 करोड़ की राशि आवंटित की गई और कई नई योजनाएं शुरू की गईं। सिंचाई के लिए नहरों की सफाई, 917 टैंक की मरम्मत और 88 चेक डैम का निर्माण किया गया। पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में भी दूध और अंडे के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

CEASI TIMES

ड्रोन दीदि ने बदली खेती की तस्वीर, तकनीक और कौशल से ग्रामीण महिलाएं बनीं सशक्त

भारत के ग्रामीण इलाकों में महिलाएं अब खेती में ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं, जो कृषि में आधुनिक बदलाव का प्रतीक बन चुका है। ये महिलाएं “ड्रोन दीदी” के नाम से जानी जाती हैं और बीज बोने, कीटनाशक छिड़कने व फसल की निगरानी जैसे कामों में दक्षता से ड्रोन चला रही हैं। इनका योगदान यह दिखाता है कि नई तकनीक न केवल उत्पादन बढ़ा रही है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को भी सशक्त बना रही है।

महिलाओं द्वारा ड्रोन का उपयोग पारंपरिक खेती में आधुनिक तकनीक के समावेश का हिस्सा है। ये "आसमान की योद्धा" खेतों में श्रम की आवश्यकता को घटाती हैं, सटीकता बढ़ाती हैं और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देती हैं।

भारत की कृषि अर्थव्यवस्था खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण रोज़गार में अहम भूमिका निभाती है। जैसे-जैसे ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है, यह खेती को डेटा-आधारित और कम श्रम वाली बनाने में मदद करेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ मजदूरों की कमी और पर्यावरणीय चुनौतियाँ हैं। इस बदलाव को व्यापक रूप देने के लिए प्रशिक्षण और ड्रोन की पहुँच को आसान बनाना जरूरी होगा।

"विकसित कृषि संकल्प अभियान" 29 मई से शुरू: खेतों तक पहुँचेगी वैज्ञानिक खेती की जानकारी

देशभर में आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने और अनुसंधान को खेतों तक पहुँचाने के उद्देश्य से "विकसित कृषि संकल्प अभियान" 29 मई से शुरू हो रहा है। इस राष्ट्रव्यापी पहल के तहत 2,000 से अधिक विशेषज्ञों की टीमें 65,000 से अधिक गांवों का दौरा करेंगी और किसानों को फसल चयन, मिट्टी प्रबंधन, सिंचाई तकनीक और प्राकृतिक खेती जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देंगी।

अभियान का उद्देश्य खेती की लागत घटाना, फसल विविधिकरण को प्रोत्साहित करना और मूल्य संवर्धन के अवसरों को बढ़ाना है। यह भारत की खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर जब इस वर्ष गेहूं, चावल, तिलहन और दालों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है।

इस अभियान की खास बात यह है कि यह दोतरफा संवाद को बढ़ावा देगा — किसान न केवल वैज्ञानिक सलाह लेंगे, बल्कि अपनी जमीनी चुनौतियाँ भी साझा करेंगे, जिससे भविष्य के अनुसंधान को दिशा मिलेगी। कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों की मदद से यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक ज्ञान की पहुँच को आसान बनाएगा।यह पहल न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाने बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक ठोस कदम है।

CEASI TIMES

डेरी इनसाइट्स

भारत टिकाऊ डेयरी विकास के लिए तीन बहु-राज्यीय सहकारी समितियाँ शुरू करेगा

भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में टिकाऊपन और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए तीन नई बहु-राज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना की घोषणा की है। ये समितियाँ पशु आहार, गोबर प्रबंधन और मवेशियों के अवशेषों के परिपत्र उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेंगी ताकि पर्यावरण-अनुकूल डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके।पहली समिति पशु स्वास्थ्य सुधार पर केंद्रित होगी।

दूसरी समिति गोबर प्रबंधन के प्रभावी मॉडल विकसित करेगी, जो अपशिष्ट को कम करने और कृषि व जैव ऊर्जा में उसके उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। तीसरी समिति मृत मवेशियों के अवशेषों के परिपत्र उपयोग पर जोर देगी, जिससे जैव-अर्थव्यवस्था को सहयोग मिलेगा और पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकेगा।

इस पहल में यह सुनिश्चित करने के प्रयास भी शामिल हैं कि कार्बन क्रेडिट से मिलने वाले लाभ वैज्ञानिक मॉडल के माध्यम से सीधे किसानों तक पहुँचें। इस पहल पर एक उच्चस्तरीय बैठक में चर्चा की गई, जिसमें एनडीडीबी और नाबार्ड के अधिकारियों ने भाग लिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि टिकाऊ और परिपत्र उपायों के माध्यम से डेयरी उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

घरेलू विस्तार के साथ वैश्विक बाजारों पर नजर: कॉमफेड

बिहार राज्य दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (कॉमफेड), जो सुधा ब्रांड के लिए जाना जाता है, देश और विदेश दोनों में अपने संचालन का विस्तार कर रहा है। ₹1,500 करोड़ के वार्षिक कारोबार वाले कॉमफेड द्वारा वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 30 लाख लीटर दूध एकत्र किया जाता है और इसे 45 लाख लीटर तक बढ़ाने की योजना है। इसमें से लगभग 18 लाख लीटर तरल दूध के रूप में बेचा जाता है, जबकि शेष दूध से विभिन्न डेयरी उत्पाद बनाए जाते हैं।

यह सहकारी संस्था संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) बाजार में भी अवसर तलाश रही है। घरेलू स्तर पर, यह पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में भी विस्तार कर चुका है, हालांकि इन प्लांटों की उत्पादन क्षमता अभी बढ़ाई जा रही है।

कॉमफेड 30,000 से अधिक दूध समितियों के नेटवर्क के माध्यम से काम करता है और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सीधे लाभ हस्तांतरण की सुविधा शुरू की है। यह अपने सदस्य किसानों के लिए ₹5 लाख का दुर्घटना चिकित्सा बीमा योजना भी लाने की योजना बना रहा है, जिससे किसान सहायता प्रणाली मजबूत होगी।

कॉमफेड ने हाल ही में अपने प्रीमियम डेयरी उत्पाद जैसे घी, गुलाब जामुन और मखाना का निर्यात अमेरिका में शुरू किया है, जो बिहटा ड्राई पोर्ट और गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है।

CEASI TIMES

सिस्टेमा.बायो और डैनोन 2030 तक 6,500 डेयरी फार्म्स पर लगाएंगे बायोडाइजेस्टर

सिस्टेमा.बायो ने वैश्विक खाद्य कंपनी डैनोन के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत 2030 तक छोटे डेयरी फार्मों पर 6,500 बायोडाइजेस्टर लगाए जाएंगे। यह पहल मोरक्को में आयोजित 17वीं अंतरराष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी (SIAM) में घोषित की गई और इसका लक्ष्य मैक्सिको, मोरक्को और भारत के फार्म हैं। बायोडाइजेस्टर पशु अपशिष्ट को बायोगैस और खाद में बदलते हैं, जिससे टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलता है और छोटे किसानों को उत्सर्जन घटाने, लागत कम करने और मिट्टी की सेहत सुधारने में मदद मिलती है।

डैनोन से जुड़े कई किसान 20 से कम गायों के साथ काम करते हैं, और बायोडाइजेस्टर उन्हें स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराएंगे और कृत्रिम उर्वरकों पर निर्भरता कम करेंगे।

यह पहल परिपत्र कृषि और जलवायु-स्थिर खेती की ओर बढ़ते वैश्विक प्रयासों को दर्शाती है। यह साझेदारी मोरक्को में डैनोन की "हलीब ब्लाडी" जैसी स्थानीय टिकाऊ कार्यक्रमों को समर्थन देती है और दुनिया भर में अधिक आत्मनिर्भर फार्म तैयार करने का लक्ष्य रखती है। पशु अपशिष्ट को उपयोगी संसाधनों में बदलकर यह प्रोजेक्ट डेयरी क्षेत्र को डीकार्बनाइज़ करने में मदद करता है और फार्म की दीर्घकालिक उत्पादकता को बढ़ाता है।

पुडुचेरी में डेयरी क्षेत्र के लिए एनडीडीबी ने प्रस्तावित किया रणनीतिक रोडमैप

हाल ही में पुडुचेरी विधानसभा में केंद्र शासित प्रदेश के डेयरी क्षेत्र के विकास को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) के चेयरमैन मीनश शाह और कार्यकारी निदेशक राजीव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एनडीडीबी टीम पुडुचेरी के पोंलाइट में आइसक्रीम प्लांट की आधारशिला रखने के लिए आई थी। ठक के दौरान एनडीडीबी ने स्थानीय डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की।

इस योजना में नस्ल सुधार कार्यक्रम, उत्पादकता वृद्धि, बाजार तक पहुंच का विस्तार और सहकारी नेटवर्क को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा, यह योजना सहकारी समितियों में काम करने वाले दुग्ध उत्पादक किसानों को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं पर केंद्रित विकास पहलों को प्राथमिकता देती है।

अधिकारियों ने पुष्टि की कि केंद्र शासित प्रदेश, एनडीडीबी के साथ मिलकर इस योजनाबद्ध विकास कार्यक्रम को लागू करता रहेगा। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव और पुडुचेरी सरकार के सचिव सहित कई प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

CEASI TIMES

डेयरी किसानों की सहायता के लिए केरल ने शुरू की पशु बीमा योजना

केरल ने डेयरी किसानों को बीमारी और पर्यावरणीय तनाव के कारण होने वाले नुकसान से आर्थिक सहायता देने के लिए पशु बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत चमड़ी रोग या अत्यधिक गर्मी से गाय की मृत्यु पर ₹37,500, बछड़े की मृत्यु पर ₹20,000 और मृत जन्म पर ₹10,000 का मुआवजा मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य किसानों के आर्थिक नुकसान को कम करना और डेयरी क्षेत्र को स्थिर बनाना है।

यह योजना नीलेश्वरम ब्लॉक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान घोषित की गई, जिसे नीलेश्वरम डेयरी विकास इकाई, मिल्मा, पशुपालन विभाग और केरल फीड्स ने मिलकर आयोजित किया था। इस अवसर पर एडयिलाकोड मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा एक नया स्वच्छ दुग्ध संग्रहण कक्ष भी उद्घाटित किया गया, जिसका उद्देश्य डेयरी उद्योग में ढांचे और गुणवत्ता में सुधार करना है। अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने किसानों के कल्याण को बेहतर बनाने के लिए एकजुट प्रयासों पर बल दिया।

यह बीमा योजना केरल की उस व्यापक योजना का हिस्सा है, जो पशु रोगों और जलवायु तनाव के खिलाफ मजबूती पैदा करने, पशु देखभाल सुधारने और राज्य भर में टिकाऊ डेयरी खेती को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।

हॉर्टिकल्चर इनसाइट्स

हरियाणा सरकार ने बागवानी विभाग की सात सेवाओं को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाया

हरियाणा सरकार ने बागवानी विभाग की सात प्रमुख सेवाओं को राइट टू सर्विस एक्ट, 2014 के तहत शामिल कर समयबद्ध और जवाबदेह सेवा प्रदान करना सुनिश्चित किया है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, बागवानी से संबंधित विभिन्न आवेदनों को तय समय-सीमा में निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। Hortnet पोर्टल पर किए गए आवेदन 21 दिनों के भीतर स्वीकृत या अस्वीकृत किए जाने चाहिए।

नर्सरी फल और नर्सरी बीज लाइसेंस जारी करने के लिए 90 दिनों की समय-सीमा तय की गई है। भौतिक सत्यापन और निधियों की उपलब्धता के बाद सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

भवांतर भरपाई योजना (BBY) के तहत स्वीकृत दावों पर प्रोत्साहन राशि का वितरण 21 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है। किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के पंजीकरण की प्रक्रिया, सभी दस्तावेज और व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। नामित अधिकारियों और पहली व दूसरी स्तर की शिकायत निवारण प्राधिकरणों को समय पर और प्रभावी सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

CEASI TIMES

बिहार ने वैज्ञानिक बागवानी और अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए बड़े कृषि सुधारों की शुरुआत की

कृषि के आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार ने कई नई पहलें शुरू कीं और महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन सुधारों के तहत, 315 नए ब्लॉक बागवानी अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए, ताकि जमीनी स्तर पर विस्तार सेवाओं को मजबूत किया जा सके। इन पहलों में किसानों को नकदी फसलों और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रति जागरूक करना शामिल है, जिसमें अरा (भोजपुर) में ₹144.72 करोड़ की कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज परियोजना प्रमुख है।

यह 16 एकड़ का संस्थान शैक्षणिक और प्रशासनिक ब्लॉक, छात्रावास, कार्यशालाएं, कर्मचारी आवास के साथ-साथ 62 उप-प्रभागीय कृषि भवनों की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे सहायक प्रणालियों को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा, एक खरीफ अभियान के तहत जागरूकता वाहन चलाए गए और किसानों को समय पर डिजिटल कृषि जानकारी देने के लिए बिहार कृषी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया।

सिंघाड़ा किसानों को बागवानी मिशन योजना में शामिल किया जाएगा

परंपरागत सिंघाड़ा (जलकटोरा) उगाने वाले किसानों के समर्थन में जिले के बागवानी विभाग ने उन्हें बागवानी मिशन योजना के तहत लाने का फैसला किया है। यह निर्णय सिंघाड़ा की खेती वाले क्षेत्रों का निरीक्षण और स्थानीय किसानों से बातचीत के बाद लिया गया है। पहली बार सिंघाड़ा उगाने वाले किसानों को एक सरकारी योजना से जोड़ा जाएगा, जिसका उद्देश्य उनकी कृषि आजीविका को सुधारना है। किसानों ने अपनी खेती की विधियां, उत्पादन लागत और चुनौतियों के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सिंघाड़ा की खेती समय-साध्य होती है। फसल कटने के बाद खेत पानी से भरे रहते हैं, जिससे वे तुरंत दूसरी फसल के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, और किसान साल में केवल एक बार ही फसल उगा पाते हैं।किसानों ने इस पहल और सहयोग को लेकर खुशी जताई और कई लोग योजना में नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं।

विभाग का लक्ष्य सिंघाड़ा उगाने वाले किसानों के लिए और भी सहायता रणनीतियां विकसित करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ ले सकें और इसके लिए वे स्थानीय कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।

CEASI TIMES

FSSAI ने राज्यों को निर्देश दिया सिंथेटिक फल कोटिंग और अवैध पकाने वाले एजेंटों पर कार्रवाई के लिए

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध पकाने वाले एजेंटों और सिंथेटिक फल कोटिंग के उपयोग के खिलाफ जांच और कड़ी कार्रवाई बढ़ाने का निर्देश दिया है। विशेष रूप से, कैल्शियम कार्बाइड के अवैध उपयोग पर रोक लगाने पर जोर दिया गया है, जो खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत प्रतिबंधित है और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है।
अधिकारियों को फल बाजारों और मंडियों में कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए कहा गया है, ताकि उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

FSSAI ने यह भी बताया कि कुछ खाद्य व्यवसायी सीधे फलों को इथेफॉन सॉल्यूशन में डुबोकर कृत्रिम पकाने का काम कर रहे हैं, खासकर केले के लिए। उन्होंने दोहराया कि इथीलीन गैस का उपयोग केवल मान्य स्रोतों से और निर्धारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार ही किया जाना चाहिए। गोदामों और संदिग्ध भंडारण स्थलों की जांच की सिफारिश की गई है, जहां कैल्शियम कार्बाइड पाए जाने पर उसे कानूनी कार्रवाई के लिए प्रमाण माना जाएगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

फार्म मेकनज़ैशन इनसाइट्स

भारत की ट्रैक्टर इंडस्ट्री में वृद्धि की तैयारी, बिक्री में मामूली गिरावट के बावजूद

भारत की ट्रैक्टर इंडस्ट्री, जो विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है, ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में घरेलू बिक्री 8.83 लाख यूनिट दर्ज की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1% की मामूली गिरावट है। गिरावट के बावजूद, इस क्षेत्र को जल्द ही 10 लाख यूनिट की वार्षिक बिक्री तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए या तो एक साल में 13.2% की वृद्धि या दो साल में 6.4% की वार्षिक वृद्धि आवश्यक होगी।

मशीनरीकरण की पहलों और कस्टम हायरिंग सेंटर जैसे साझा उपयोग मॉडल से छोटे किसान ट्रैक्टर का लाभ बिना सीधे स्वामित्व के उठा सकते हैं।वित्तीय वर्ष 2025 में बाजार का प्रदर्शन मिश्रित रहा। कुछ ब्रांडों ने मध्यम बढ़त देखी, जबकि कुछ की बिक्री घट गई। महिंद्रा ने कुल बिक्री में अग्रणी स्थान हासिल किया, इसके बाद स्वराज और सोनालिका ने अच्छी प्रदर्शन दी। वहीं, जॉन डियर ने भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जो निर्माताओं के बीच विविध गति को दर्शाता है।

उच्च बिक्री की ओर संक्रमण मांग के अलावा कई अन्य कारकों पर निर्भर करेगा। नियमित मानसून, ग्रामीण ऋण की बेहतर उपलब्धता, और पूर्वी भारत जैसे क्षेत्रों में मशीनीकरण की गहराई बाजार विस्तार के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

CEASI TIMES

महाराष्ट्र ने कृषि पहुंच बढ़ाने के लिए खेतों की सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई तय की

महाराष्ट्र सरकार ने एक नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सभी खेतों की सड़कों की चौड़ाई कम से कम तीन मीटर होनी चाहिए। इसका उद्देश्य कृषि मशीनरी की आवाजाही को बेहतर बनाना, सिंचाई तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना और उत्पादों के कुशल परिवहन को बढ़ावा देना है। यह बदलाव बिना पंजीकृत, संकरी खेतों की पगडंडियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि मशीनरीकरण बढ़ रहा है।

इस निर्णय के तहत खेतों की सड़कें अब 7/12 भूमि के टाइटल दस्तावेजों में "अन्य अधिकार" खंड के अंतर्गत दर्ज की जाएंगी। इसमें मौजूदा और नई दोनों तरह की खेतों की सड़कें शामिल होंगी, जिससे जमीन के स्वामित्व में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन उन्हें कानूनी मान्यता मिलेगी।

अधिकारी बताते हैं कि ये सड़कें आमतौर पर कच्ची होती हैं, फिर भी ये दैनिक कृषि कार्यों के लिए बेहद जरूरी हैं। जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित सभी आवेदन 90 दिनों के अंदर निपटाएं, ताकि समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। ग्रामीण मार्गों को औपचारिक रूप देने का लक्ष्य किसानों की लॉजिस्टिक्स को आसान बनाना और महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्रों में पहुंच बेहतर करना है।

उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर स्वामित्व में तेज़ बढ़ोतरी, कृषि यंत्रीकरण को मिल रहा बढ़ावा

उत्तर प्रदेश में खेती के तरीकों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पिछले आठ वर्षों में ट्रैक्टर स्वामित्व में 62% की वृद्धि हुई है। 2016–17 में जहाँ 88,000 ट्रैक्टर थे, वहीं 2024–25 में यह संख्या बढ़कर 1,42,200 हो गई है। यह बदलाव राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यंत्रीकृत खेती की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है और आधुनिक तकनीकों पर किसानों के बढ़ते विश्वास को भी दिखाता है।

यह यंत्रीकरण कृषि के आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों का परिणाम है। प्रशिक्षण, जागरूकता और कृषि विज्ञान से जुड़े सहयोग ने इस प्रक्रिया को गति दी है। बेहतर सिंचाई, समय पर इनपुट्स और विविध फसलें खासकर छोटे और मध्यम किसानों के लिए फायदेमंद रही हैं।

ट्रैक्टर आधारित उपकरणों की पहुंच ने बुआई और फसल अवशेष प्रबंधन में उल्लेखनीय असर डाला है। सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता ने लागत घटाने में मदद की है, जबकि दालों, तिलहनों और गन्ने में बेहतर पैदावार से किसानों की आमदनी में वृद्धि हुई है।

CEASI एक्टिविटीज

उत्तर-पूर्व डेयरी सम्मेलन

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI) ने डेयरी विकास निदेशालय, असम सरकार के सहयोग से 15 मई 2025 को उत्तर-पूर्व डेयरी सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 36 संगठनों के 150 से अधिक प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें सरकारी विभाग, डेयरी और कृषि उद्योग, शैक्षणिक संस्थान और किसान समूह शामिल थे।

इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई श्रीमती पंचाली काकती, एसीएस, निदेशक, डेयरी विकास, असम; श्री एम. एस. मणिवन्नन, आयुक्त एवं सचिव, पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग, असम सरकार; तथा मुख्य अतिथि श्री बी. कल्याण चक्रवर्ती, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्रम कल्याण विभाग, असम सरकार ने। आईसीआईसीआई, नाबार्ड और एसबीआई के विशेषज्ञों ने भी चर्चाओं को और समृद्ध किया।

मुख्य सत्रों में उत्तर-पूर्व में संगठित डेयरी क्षेत्र की भूमिका, सहकारी मॉडल, तकनीकी एकीकरण, मूल्य संवर्धन, और बाजार से जुड़ाव के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चर्चा हुई। दूध उत्पादन में एआई के उपयोग, और डेयरी किसानों के लिए माइक्रोफाइनेंस और बीमा की भूमिका को लेकर भी गहन चर्चा की गई। कौशल विकास को एक केंद्रीय विषय के रूप में लिया गया, जिसमें नए आजीविका अवसरों और डेयरी मूल्य श्रृंखला में स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया।

सम्मेलन ने डेयरी क्षेत्र में सहयोग के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान किया, जिसमें सरकार, उद्योग और जमीनी स्तर के संगठनों के प्रतिनिधियों ने अनुभव और सर्वोत्तम प्रक्रियाएं साझा कीं। इन संवादों और अनुभवों ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की चुनौतियों और अवसरों को बेहतर समझने में मदद की और भविष्य की रणनीतियों का मार्ग प्रशस्त किया।इंडस्ट्री पार्टनर बेनी इम्पेक्स और प्रायोजक प्रॉम्प्ट व ज़्यूसर इंडिया के सहयोग से आयोजित यह सम्मेलन क्षेत्र में एक मजबूत और आत्मनिर्भर डेयरी प्रणाली के निर्माण के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

CEASI एक्टिविटीज

क्लस्टर खेती और बागवानी प्रबंधन में महिला किसानों को सशक्त बनाने की पहल, करनाल में प्रशिक्षण कार्यक्रम

करनाल में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI) ने 30 महिला किसानों के लिए HP-SHIVA परियोजना के तहत क्लस्टर खेती और आधुनिक बागवानी पद्धतियों पर केंद्रित 3-दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण-सह-अवलोकन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह कार्यक्रम वर्तमान में जारी है।

इस पहल के तहत, प्रतिभागियों को व्यावहारिक अनुभव देने के लिए कुरुक्षेत्र स्थित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र और लाडवा स्थित उपोष्ण फल केंद्र का दौरा कराया जा रहा है। इन दौरों का उद्देश्य प्रतिभागियों की टिकाऊ बागवानी प्रथाओं, परागण प्रबंधन और सामूहिक खेती की समझ को बढ़ाना है, जिससे वे अपने खेती समुदायों में नवाचार अपनाने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त कर सकें।

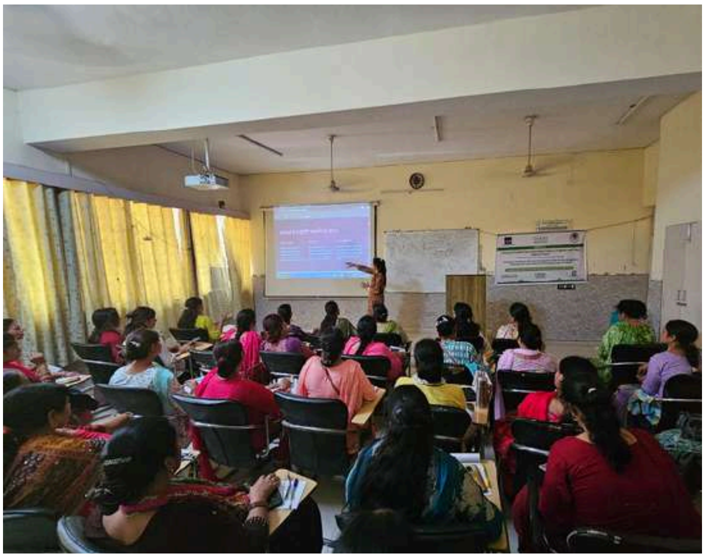

हम कौन हैं

"सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स (CEASI)" एक स्वायत्त संगठन है, जो "एग्रीकल्चर स्किल कौंसिल ऑफ़ इंडिया (ASCI)" के अधीन कार्य करता है। ASCI, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत काम करता है और इसका उद्देश्य किसानों, श्रमिकों, स्व-रोज़गार करने वाले पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण करना है। यह कार्यक्रम कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए तैयार किया गया है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों का एक शीर्ष संगठन है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेचानिज़शन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)

CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEFMI
Centre of Excellence for Farm Mechanization Skills in India

CEHSI
Centre of Excellence for Horticulture Skills in India